भारत-अमेरिका व्यापार

बंदिशें दूर हों, बातचीत आगे बढ़े

लॉरिंडा कीज लौंग

भारत और अमेरिका के बीच भविष्य में कभी न कभी 'एकदम' मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत हो सकती है लेकिन इससे पहले कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को सुलझाने में वर्षों लग सकते हैं। अधिक मुक्त तथा संतुलित व्यापारिक ढांचा बनाने की दिशा में लगातार प्रगति आवश्यक है। अमेरिका के व्यापार उपप्रतिनिधि करन भाटिया यह राय जताते हैं।

भाटिया ने जून में स्पैन से साक्षात्कार में कहा, ''मैं आशावान हूं।'' उनसे यह साक्षात्कार अमेरिका और भारत के बीच-धीरे-धीरे बढ़ रही व्यापारिक बातचीत के बारे में उनके भारत दौरे के मौके पर किया गया। अमेरिका मंत्रिस्तरीय व्यापार वार्ता भारत के अलावा सिर्फ चीन और यूरोपीय संघ के साथ कर रहा है। इस वर्ग में भारत को पिछले साल नवंबर में व्यापार नीति फोरम के गठन के बाद शामिल किया गया था और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन यदि इसका कुछ महत्व है तो नतीजे मिलना जारी रहना चाहिए। इसके लिए व्यापार और निवेश के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को सचमुच दूर करना होगा।"

अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि करन भाटिया

अजीत कुमार © ए.पी.-डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.

राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को दुगुना करने के लक्ष्य को तीन साल के भीतर हासिल करने का इरादा जताया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, लगभग तीस अरब डॉलर है। भाटिया के अनुसार इस अपेक्षाकृत छोटे आधार के कारण व्यापार दुगुना करने के लक्ष्य को पाना आसान होगा। भारत के मुकाबले चीन के साथ अमेरिका का व्यापार सालाना 285 अरब डॉलर है। उनके अनुसार इस लिहाज से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार दुगुना करने का मतलब सिर्फ तीस अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी है, इसलिए यह लक्ष्य ज्यादा व्यावहारिक है।

इसका मतलब यह नहीं है कि इसे पूरा करने में बाधाएं नहीं आएंगी। उनके अनुसार, ''यदि उस लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना होगा। मैं बाधाएं हटाने का पक्षधर हूं, दोनों तरफ से व्यापारिक अड़चनों का समाधान निकालने से ही हमारे व्यापारी सुचारू ढंग से भारत में निवेश कर पाएंगे और भारतीय व्यापारी भी अमेरिका में आसानी से निवेश कर सकेंगे।

ऐसे में क्या कभी मुक्त व्यापार समझौता साकार हो पाएगा? भाटिया का जवाब है अभी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें हमें बैठकर सुलझाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भारत में कृषि क्षेत्र अभी तक बहुत ज्यादा संरक्षित है और हमारे मुक्त व्यापार समझौते की खासियत ही यह है कि उसके अंतर्गत तटकर की दरों को शून्य करना पड़ता है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में भी गहराई से ध्यान देना होगा। इस तरह कुछ मामले ऐसे हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं और जिन्हें सुलझाने में महीनों के बजाय कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन क्या मैं उस दिन की कल्पना कर सकता हूं जब अमेरिका और भारत, मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत करेंगे? बेशक"

भाटिया के इस आशावाद का एक कारण पिछले साल, भारत और अमेरिका के बीच नागरिक उड्डयन से संबंधित (खुला आकाश) समझौते में उनकी भूमिका है। उस समय वह नागरिक उड्डयन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। भाटिया के अनुसार, कभी-कभी जब सही लोग किसी मुद्दे पर काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है और मेरे हिसाब से खुला आकाश समझौते का भी यही राज है। अमेरिका और भारत के समान हितों वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और खुला आकाश समझौते पर हमने अवधारणा के स्तर पर ही काफी गहराई से विचार-विमर्श किया था। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में। लेकिन यह बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हो गया। भारत भी नागरिक उड्डयन में सुधार करना चाहता था और इसे और उदार बनाकर इसमें प्रतियोगिता को बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करना चाह रहे हैं, खासकर नए व्यापार नीति मंच को स्थापित करने के क्षेत्र में।

उदाहरण के लिए उनका कहना है कि अमेरिका और भारत का साझा हित जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निहित है। इसके साथ ही अमेरिका और भारत दोनों ही यह मानते हैं कि बुनियादी ढांचे और कृषि व्यापार जैसे क्षेत्रों में निवेश बाधित करने वाली नीतियों को और उदार बनाया जाना चाहिए, ताकि इसके विकास से दोनों को फायदा हो पाए।

व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापारिक संभावनाएं लगातार आकर्षित करती रहें। भाटिया ने कहा, "मुझे लगता है कि इस बारे में अभी फैसला होना बाकी है। यहां काफी उत्साह था, उसका एक कारण राष्ट्रपति की भारत यात्रा थी और उससे संबंधों में गति आती है। लेकिन यदि अमेरिकी कंपनियां तटकर अथवा गैर तटकर बाधाओं में उलझ गईं तो वे बहुत तेजी से दुनिया के अन्य हिस्से में व्यापार की गुंजाइश तलाशेंगी जहां उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना न करना पड़े। वैसे भी भारत, दक्षिण-पूर्वी एशिया की उन अर्थव्यवस्थाओं से इतना दूर भी नहीं है जो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और जहां उदारीकरण हो रहा है। इसलिए भारत को अपने क्षेत्र में प्रतियोगी बने रहना होगा।" उनके अनुसार, इस बातचीत को लेकर अमेरिकी कंपनियों में बहुत उत्साह है। अमेरिका और भारत सरकार के बीच वरिष्ठ स्तर पर बातचीत से भी वे खुश हैं। लेकिन वे हमसे नतीजे की उम्मीद रखते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध या फिर ऐसे प्रतिबंध जो यहां व्यापार करने या निवेश के लिए निरुत्साहित कर रहे हैं, जैसे नियमन संबंधी बाधाएं।"

साभार: हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी

भाटिया उदाहरण के तौर पर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उल्लेख करते हैं। यह बड़ी मोटरसाइकिलें बनाने वाला अमेरिकी उत्पादक है और विशेषज्ञ निर्यातक भी। इसके उत्पादों की दुनियाभर के बाजारों में पूछ है। भाटिया का कहना है, "बड़ी मोटरसाइकिलों पर भारत में तटकर की दर शत प्रतिशत है और इतना ही नहीं, उन पर नियमन संबंधी बाधाएं, उत्सर्जन के मानक आदि भी लागू हैं। इनके कारण आप सिर्फ बहुत छोटी-छोटी मोटरसाइकिलों का आयात ही कर सकते हैं।"

"ऐसा भी नहीं है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए ऐसा कर रहा हो। वे हार्ले जैसी बड़ी मोटरसाइकिलें बनाते ही नहीं। नौकरशाही को इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए मनाया जा रहा है। तटकर संबंधी बाधाओं और गैरतटकर संबंधी मुद्दों पर कार्रवाई और भी कठिन है। आगे बढ़ती व्यापार वार्ता में अमेरिका को ऐसे मुद्दों पर दबाव डालना होगा क्योंकि हार्ले जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में पैठ बनानी चाहिए और भारतीय उपभोक्ताओं को अमेरिकी उत्पाद मिलने चाहिएं।" अमेरिकी व्यापार उप प्रतिनिधि के मुताबिक, "हमारा बाजार भारतीय उत्पादों के लिए बहुत ज्यादा खुला है, दरअसल हम अपने जीएसपी (वरीयता की सामान्य प्रणाली) कार्यक्रम के जरिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रखते हैं। लेकिन हमें भारत द्वारा बदले में बाजार खोलने की कार्रवाई होती दिखनी चाहिए।" भाटिया को हालांकि 20 वर्ष पहले के मुकाबले अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह लगता है कि भारत सरकार भी परिवर्तन के लिए काम कर रही है। उनके अनुसार, "सरकारों के लिए अपनी ऐसी एजेंसियों से काम करवाना हमेशा ही चुनौती भरा रहता है, जो कभी-कभी आगे बढ़ने में सुस्त रहती हैं।"

दूसरी तरफ भारतीय प्रोफेशनलों की अमेरिका यात्रा को सुगम बनाना भी महत्वपूर्ण मुद्दा है और वहां अमेरिकी बैंकिंग, कृषि और औद्योगिक उत्पादों संबंधी नियमों पर भारत सरकार ने चिंता जताई है। भाटिया के अनुसार, "हम इन मुद्दों पर भी संवेदनशील होने का प्रयास करते रहे हैं।" इसका एक परिणाम भारतीय आम के अगले साल अमेरिका द्वारा आयात की संभावना के रूप में आया है। इस मुद्दे पर 17 साल से बातचीत चल रही थी।

भाटिया के अनुसार, "सच यह है कि वैश्विक व्यापार से दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए। व्यापारिक अधिकार के लिहाज से फिलहाल अमेरिका के मुकाबले भारत फायदेमंद स्थिति में है। हम भारत से द्विपक्षीय व्यापार में अरबों डॉलर का घाटा उठा रहे हैं। क्या यह समस्या है ? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अमेरिकी कंपनियों के लिए यहां बराबरी के मौके चाहता हूं और उनके लिए बाजार को और अधिक खोले जाने की आवश्यकता है ताकि वे खुलकर बाजार होड़ में हिस्सा ले सकें। आखिरकार मैं द्विपक्षीय संबंधों को फलता-फूलता देखना चाहता हूं।"

करन भाटिया के अनुसार अमेरिकी कंपनियों की अपेक्षा है कि भारत हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल जैसे उत्पादों से आयात बाधाएं दूर करे।

भाटिया के पिता गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से 1960 के दशक में अमेरिका चले गए थे। भाटिया कहते हैं, "मैं अमेरिका में बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय का हिस्सा हूं जो अमेरिका में सरकार और उद्योग परिदृश्य से जुड़े लोगों का भारत में मौजूद आर्थिक संभावनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी है।"

उनके अनुसार, "भारतीय मूल के अमेरिकी होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई काम अलग तरीके से करते हैं। लेकिन भारत में उपलब्ध संभावनाओं पर आप शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार जब यह तय करने का मौका आता है कि किस देश पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो बातचीत के लिए उपलब्ध सीमित समय में शायद भारत को कुछ अधिक मौका मिल जाता है। लेकिन ऐसा भी तभी तक संभव हो पाता है जब तक बात आगे बढ़ने की गुजांइश दिखे।" □